[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

रखता है । विदेशी पर्यटक प्रति वर्ष हजारों की संख्या में यहां आते है । उनके लिए न तो कोई हवाई सेवा की व्यवस्था है और न दिल्ली से जैसलमेर तक के लिए रेलवे की व्यवस्था ।

प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सन् 1974 में पोकरण अणु विस्फोट के अवसर पर जब जेसलमेर पहंची और वहां के पुराने भवनों की कारीगिरी एवं शिल्पकला देखी तो वह बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने पुराने भवनों को राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कराया और जेसलमेर पर्यटन की दृष्टि से भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे में आया ।

जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ने के लिए फलौदी से कोलायत 110 किलोमीटर नई रेलवे लाइन का बनाना आवश्यक है । जोधपुर रियासत ने फलौदी से कोलायत रेलवे लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण सन् 1950 में पूरा कर दिया था । जोधपुर रियासत भी उक्त रेलवे लाइन को तीस साल पहले बनाना चाहती थी परन्तु आजादी के तीस सालों के बाद भी वहां उक्त रेलवे लाइन के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई है और वित्तीय साधनों की कठिनाई बतला कर आवश्यक रेलवे लाइन का पिछड़े क्षेत्रों में निर्माण नहीं किया जा रहा है जिस के कारण राजस्थान प्रांत के सीमावर्ती क्षेत्रों में घोर असंतोष है ।

फलौदी एवं कोलायत क्रमशः जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में आए हुए हैं । अतः जेसलमेर जिले के साथ साथ जोधपुर एवं बीकानेर जिले भी इस रेलवे लाइन के बनने से जुड़ जाएंगे ।

उक्त क्षेत्र खनिज की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है । जिप्सम, बेंटोनाइट, रॉक फास्फेट, पीला पत्थर, चूना एवं फलौदी में नमक का पर्याप्त भंडार है ।

राजस्थान नहर का पानी इस क्षेत्र में दो तीन साल में आने वाला है और इस क्षेत्र को हरा भरा करने वाला है ।

अतः रेलवे मंत्री से पुरजोर मांग है कि फलौदी से कोलायत तक 110 किलोमीटर रलवे लाइन देश के पिछड़े सीमावर्ती क्षेत्र में स्वीकृति दे कर सन् 1981–82 में शुरु किए जाने के आदेश फरमा कर पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र की जनता की आवश्यक मांग की पूर्ति करें ।

(iv) NEED FOR AN ADDITIONAL RAIL RESERVATION COUNTER AT BOMBAY FOR BOMBAY-AHMEDABAD ROUTE.

श्री मोतीलाल आर० चौधरी (मेहसाना): बम्बई और अहमदाबाद के बीच आने जाने के लिये आये दिन रेलगाड़ियों में ज्यादा से ज्यादा भीड़ रहती है, विशेषकर गर्मी के दिनों में तो और भीड़ बढ़ जाती है । सबसे बड़ी समस्या पर्याप्त मात्रा में आरक्षण टिकट घरों का न होना है । जिस प्रकार अहमदाबाद में एक नया रिजर्वेशन काउन्टर खोला गया है, उसी प्रकार बम्बई सेन्ट्रल पर भी खोला जाना चाहिये जिससे भीड़ कुछ कम हो सके । किसी भी दिन यात्री आरक्षण के लिये जाते हैं तो कतारों में घंटों तक खड़ा रहना पड़ता है और रिजर्वेशन की लंबी सूची बनी पड़ी रहती है । इसलिये यात्रियों की सुविधा के लिये बम्बई सेन्ट्रल पर एक रिजर्वेशन काउन्टर अति शीघ्र खोला जाना चाहिये । रिजर्वेशन में जो बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार चल रहा है उसे सुलझाने के लिये रिजर्वेशन फार्म पर क्रमांक नं० और दिनांक भी डाला जाना चाहिये और इसका विवरण रजिस्टर में भी होना चाहिये जिससे कि बाहर के दलालों के द्वारा भ्रष्टाचार के जरिये तुरन्त रिजर्वेशन कराने वालों को पकड़ने में फ्लाइंग स्केवड को सहूलियत मिल सके । कुछ दिन पूर्व अहमदाबाद स्टेशन पर एक सरकारी कर्मचारी के परिवार को जो खाली जगह देखकर रेल में बैठा था उसे दलालों द्वारा पीटा गया । इस प्रकार की घटनाओं

की पुनरावृत्ति न हो जिये तुरन्त कड़ी व्यवस्था की जाय जिससे गर्मी के दिनों में भीड़ कम करने के लिये जो विशेष ट्रेन चलायी जा रही है उनका सही लाभ यात्रियों को सरलता से मिल सके ।

मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में उचित उपाय किए जायेंगे ।

(v) NEED TO CONTINUE THE PAYMENT OF PROJECT ALLOWANCE TO EMPLOYEES OF FARAKKA PROJECT.

SHRI ZAINAL ABEDIN (Jangipur): Sir, under Rule 377 I raise the following matter of urgent public importance:—

Farakka project authorities have announced discontinuance of payment of project allowance to the project employees with effect from April, 1981, Without any valid reason. The project allowance at the rate of 20 per cent was sanctioned to the project employees and workers on account of disadvantageous conditions prevailing in the area like lack of marketing facilities, medical and schooling facilities, etc. As and when the conditions improved, the project allowance was reduced from 20 per cent to 15 per cent. But while the project is completed, disadvantages, mainly, of high cost of living due to heavy influx of people into the area will persist. Till the amenities and facilities are not made easily available to the workers by proper upliftment of the social environment within the project area and the economic stability is restored, there is no reason why the project allowance should be discontinued. furthermore, the workers engaged at the deposit work of N.T.P.C. Ganga Brahmaputra Link survey works and some works of State Irrigation Department are being paid the project allowance. Almost all the trade unions functioning in the Farakka project have unanimously demanded that project allowance at the rate of 15 per cent should be continued. This is a just demand. I, therefore, urge upon the Government to pass orders to the Farakka Barrage authorities to continue the payment of project allowance to the employees and workers of the project.

(vi) ALLEGED SMASHING OF A PHOTOGRAPH OF DR. AMBEDKAR IN KANPUR BY A POLICE SUB-INSPECTOR.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : एक ओर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की समस्या के प्रति सदन चिन्तित है और सर्वसम्मति से उनके हितों की रक्षा के लिय प्रस्ताव पास करती है, दूसरी ओर प्रशासन द्वारा उनका ठीक उल्टा किया जा रहा है और इस तरह की कार्यवाही की जा रही है जिससे देश के करोड़ों दलितों को चोट पहुंचे । इसी तरह की एक घटना का जिक्र मैं करना चाहता हूं ।

कल दिनांक 26 अप्रैल, 1981 को मेरा कार्यक्रम डा. अम्बडकर जयन्ती के सिलसिले में कानपुर में था । एक जगह जयन्ती समारोह में भाग ले कर दूसरी जगह पर गड़रिया पुरवा में जब गया तो देखकर दंग रह गया कि वहां डाक्टर अम्बेडकर का चित्र टूटा पड़ा है । महिलायें रो रही थीं । जब कारण पूछा तो पता चला कि फजलगंज थाने के एक सब-इंस्पेक्टर और दो सिपाही आये । सब-इंस्पेक्टर ने लात से ठोकर मार कर डाक्टर अम्बेडकर की फोटो को चकनाचूर कर दिया । आयोजकों को बुरी तरह पीटा । महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया । इसके पहले भी अम्बेडकर डकर स्टडियम, दिल्ली में डा. अम्बेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था । आजादी के तैंतीस वर्षों के बाद जब इस तरह की घटना घटी और संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर को इस तरह अपमानित किया जाय तो यह देश के लिय कलंक की बात है । लोगों ने बताया कि तीनों शराब पीकर नशे में चूर थे । नगर के पुलिस चीफ के